**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 389

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य के लिए प्रेरणा**

**389. श्री विनय दीनू तेंदुलकरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों और कर्मचारियों को अनुसंधान कार्य के लिए आकर्षित और प्रेरित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा यूएसए, जापान, यू॰के॰ और अन्य विकसित देशों के विश्वविद्यालयों की तर्ज पर अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार अनुसंधान के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए विदेशी संस्थानों के साथ करार करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनेक योजनाएं, पुरस्‍कार, फैलोशिप, पीठ और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनके तहत उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाओं के साथ-साथ उनमें कार्यरत संकाय सदस्‍यों को स्‍वदेशी भाषाओं के पुन: प्रवर्तन और संवर्धन सहित सभी विषयों के ज्ञान के अधिकतर सभी क्षेत्रों में गुणवत्‍ता अनुसंधान शुरू करने के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं में निम्‍नवत; शामिल हैं:

(i) उत्‍कृष्‍टता क्षमता वाले विश्‍वविद्यालय

(ii) विशेष क्षेत्र में उत्‍कृष्‍टता क्षमता वाले केंद्र (सीपीईपीए)

(iii) विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

(iv) शिक्षकों हेतु अनुसंधान परियोजनाएं

(v) मूल विज्ञान अनुसंधान

(vi) अंतर-विश्‍वविद्यालय केंद्रों की स्‍थापना

वर्ष 2014 के लिए, भारत के राष्‍ट्रपति ने केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के विजिटर के रूप में (i) सर्वोत्‍तम अनुसंधान हेतु विजिटर पुरस्‍कार और (ii) सर्वोत्‍तम नवाचार हेतु विजिटर पुरस्‍कार नामक पुरस्‍कारों की शुरूआत की है, जिनके परिणामस्‍वरूप अनुसंधान और नवचार हेतु केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों के बीच स्‍वस्‍थ प्रतिस्‍पर्धा शुरू हुई है।

(ख) से (घ): भारत सरकार की ओर से, यूजीसी, भारत और विदेशी देशों के बीच विभिन्‍न सहयोगात्‍मक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्‍वयन कर रही है। यूजीसी, यूएसए, यूके, इजरायल, नार्वे और न्‍यूजीलैंड जैसे देशों के साथ संयुक्‍त अनुसंधान कार्यक्रम संचालित कर रही है और यूएसए में पोस्‍ट डॉक्‍टरल रिसर्च हेतु रमन फैलोशिप, हंगरी के साथ स्टिपेंडियम हंगरीकम नामक अध्‍येतावृत्ति कार्यक्रम, परियोजना आधारित कार्मिक विनियम कार्यक्रम, वैज्ञानिक विनियम कार्यक्रम और उच्‍चतर शिक्षा में इंडो-जर्मन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्‍यम से छात्रों, अनुसंधान स्‍कॉलर और संकाय की मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया है। भारत में उच्‍चतर शिक्षा संस्‍थाएं अनुसंधान हेतु अनेक प्रख्‍यात विदेशी विश्‍वविद्यालयों के साथ कार्य करने में सफल रही हैं।

मुख्‍य सहयोगात्‍मक कार्यक्रमों के तहत प्रदान की गई परियोजनाओं की संख्‍या निम्‍नवत है:

1. इंडो-यूएस: 40 संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएं (20 भारत नेतृत्‍व और 20 यूएस नेतृत्‍व)

2. यूजीसी- यूकेआईईआरआई : 86 संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएं

3. इंडो- नार्वें - 13 संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएं

4. इंडो- जर्मन - 7 संस्‍थागत साझेदारी

5. इंडो - न्‍यूजीलैंड - 7 संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएं

6. इंडो - इजरायल - 40 संयुक्‍त अनुसंधान परियोजनाएं

7. रमन फैलोशिप - 453 फैलोशिप

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय और विदेशी शैक्षिक संस्‍थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग के मानदंडों का अनुरक्षण और संवर्धन) विनियम 2016, 11 जुलाई, 2016 को अधिसूचित किए गए थे। ये विनियम भारतीय शैक्षिक संस्‍थाओं, तकनीकी संस्‍थाओं को छोड़कर, के साथ सहयोग के माध्‍यम से भारत में संचालित सभी विदेशी शैक्षिक संस्‍थाओं पर लागू है। ये विनियम भारतीय उच्‍चतर शैक्षिक संस्‍थाओं को प्रख्‍यात विदेशी शैक्षिक संस्‍थाओं के साथ शैक्षिक सहयोग बनाने को बढ़ावा देते हैं।